

पानी की बबंदी पर लगाएंगे एडीएम-एसडीएम

टैकरों की व्यवस्था और शिकायतों के समाधान के लिए तहसीलदार विचक रिस्पांस टीम के रूप में काम करें : आतिशी

पायनियर समाचार सेवा | नई दिल्ली

भीषण गर्मी के बीच जल संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत पूर्धी दिल्ली में पाइप लाइन से पानी की बबंदी को रोकने के लिए एडीएम और एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपे गई है। राजस्व मंत्री आतिशी ने अदेश जारी कर मुख्य सचिव को इस पर अमल करने को कहा है। ये अधिकारी पानी की पाइप लाइनों की नियन्त्रण करेंगे।

कहीं पर लोकजन मिलता है तो 12 घंटे के अंदर उसके दुरुस्त करेंगे। इसके अलावा, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारियों की एक टीम भी तैयार की जाएगी, जो पानी के टैकरों की व्यवस्था और इसके संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए विचक रिस्पांस टीम के रूप में कार्य करेंगे।

आतिशी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि रिचार्स से पानी की बबंदी को रोकने के लिए एन रायर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मानिटरिंग की जाए। इसकी मानिटरिंग के लिए एडीएम और एसडीएम की स्पेशल टीमें तैयार की जाएं। ये टीमें मुख्य जल स्रोत से बाहर ट्रीटमेंट प्लांट और बहां से पारामिक यूजीआर तक मैन बाहर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की मानिटरिंग करेंगी।

राजस्व ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि मानिटरिंग के दौरान प्रमुख पाइप लाइनों में कोई भी लोकेशन मिलता है तो उसे 12 घंटे के भीतर ठीक किया जाए। साथ ही पानी के टैकरों की व्यवस्था और पानी से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए तहसीलदार और अन्य अधिकारी विचक रिस्पांस टीम के रूप में काम करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी टीमें रोजाना शाम 5 बजे तक नियन्त्रण की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।



जल मंत्री आतिशी

आतिशी के झूठे बयानों का पर्दाफाश : एलजी

सीधी को कार्यवाई का दिया निर्देश

एलजी ने मुक्त नहर से टैकर माफिया द्वारा पानी चोरी करने के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बारे में सरकार से एक रिपोर्ट भी सौंपें की कहा है। राजनिवास ने दावा कि जल मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों राजधानी में ही रही पानी की लिटल कार्पोरेशन सरकार पर फोड़ा था। उन्होंने अपने काल्पनिक दावों को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जारी मामले में हरियाणा सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर आधारित किया। जिस हलफनामे पर उन्होंने भरोसा कर बयान दिया था, उसे सरसरी तौर पर पढ़ने से भी उनके झूठे बयानों का पर्दाफाश हो जाता है। उपराज्यपाल के मुताबिक, विचार दस्तावेजों को देखने से यह सफाई हो जाता है कि हरियाणा राज्य लगातार दिल्ली को अपने अवार्टित हिस्से से अधिक पानी की अपार्टिंग कर रहा है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल

कार्यालय के एक अधिकारी ने

बताया कि उच्चतम न्यायालय ने

अम आदमी पार्टी सरकार को

फैक्टर लगाते हुए पूछा है कि

उसने राजधानी में पानी की चोरी, रिसाव को रोकने के

लिए क्या किया है। कोर्ट ने इस बारे में सरकार से

एक रिपोर्ट भी सौंपें की कहा है। राजनिवास ने दावा

कि जल मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों राजधानी में ही

रही पानी की लिटल कार्पोरेशन सरकार पर

फोड़ा था। उन्होंने अपने काल्पनिक दावों को इस

संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जारी मामले में हरियाणा

सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर आधारित किया।

जिस हलफनामे पर उन्होंने भरोसा कर बयान दिया था,

उसे सरसरी तौर पर पढ़ने से भी उनके झूठे बयानों का

पर्दाफाश हो जाता है।

उपराज्यपाल के मुताबिक, विचार दस्तावेजों को देखने से यह सफाई हो जाता है कि हरियाणा राज्य लगातार दिल्ली को अपने अवार्टित हिस्से से अधिक पानी की अपार्टिंग कर रहा है।

उपराज्यपाल के लिए तहसीलदार और अधिकारी विचक रिस्पांस टीम के रूप में काम करें। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी टीमें रोजाना शाम 5 बजे तक नियन्त्रण की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल

कार्यालय के एक अधिकारी ने

बताया कि उच्चतम न्यायालय ने

अम आदमी पार्टी को लेकर एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

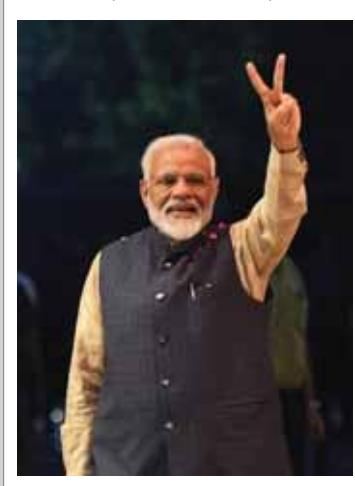
एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को लेकर

एक अधिकारी को ल

मोदी सरकार महत्वपूर्ण मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार में भाजपा ने महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने का निर्णय किया है। भाजपा द्वारा अपनी धर्म शक्ति और गठबंधन साझेदारी, जैसे तेलगु-देशम पार्टी-तेदेपा व जनता दल युनाइटेड-जदू व के कथित दबाव के बावजूद केन्द्र सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने का निर्णय किया है। इस प्रकार भाजपा ने सत्ता पर अपने केन्द्रीकरण की गारंटी की है जिससे वह महत्वपूर्ण मंत्रालयों के जरूरी नियंत्रण स्थान पर सकेंगे। निश्चय रूप से इससे नीतिगत निरंरक्षा तथा सुशासन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही 'लाल फौंटोशाही' पर लगाम रख कर सरकार के एंडेंड का तेजी से क्रियावाचक भी सुनिश्चित होगा। महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखने से भाजपा जनता में अपनी उपलब्धियों तथा सुशासन की क्षमता का प्रचार कर सकेंगी जो सत्ता तथा अपना समर्थन आधार बनाए रखने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्षी दलों को आसंगा है कि शायद भाजपा नीत राष्ट्रीय नीतिगत गठबंधन-राजग के गठबंधन सहयोगी रूप से असहमति है। संबंधों में इस कारण तनाव पैदा हो सकता है तथा वे ज्यादा साझेदारी की मांग भी कर सकते हैं। हालांकि, मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों ने केवल शपथ ले ली है, बल्कि उन्होंने मंत्रालयों में अपना कामकाज भी संभाल लिया है। इसे देखते हुए फिल्हाल ऐसी आशंका निराकार लगती है कि भाजपा नीत राष्ट्रीय नीतिगत गठबंधन-राजग के एंडेंड का गठबंधन सहयोगी के कुछ अपतियां की थीं। जहां तक गठबंधन सहयोगियों को ओर से उनके क्षेत्रीय विकास



विषयों के लिए नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में गठबंधन सहयोगियों की राय भिन्नों विकास का पूर्ण समान किया जाएगा। गठबंधन की स्थिति पर आशंका व्यक्त करने वालों को गौर करना चाहिए कि अतीत की तुलना में इस बार गठबंधन के प्रमुख दल- भाजपा की संख्या बहुत अधिक है और गठबंधन सहयोगी अनेक अन्य कारणों से भी इससे बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायदू अंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और भाजपा उनकी सरकार में शामिल है। विवार में जदू नेता नीतिश कुमार राजग गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और अगले साल हाने वाले विधानसभा चुनाव में भी वे राजग का 'मुख्यमंत्री चेहरा' होंगे। दोनों नेता अपने राज्यों के विकास के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोग और सहयोग चाहते हैं। मोदी ने न केवल इसका वादा किया है, बल्कि नायदू के शपथ ग्रहण समरोह में उनकी उपरिधि इसकी गारंटी भी है। इसके साथ ही पिछले दस वर्ष में मोदी सरकार द्वारा देश के विकास की त्वरित गति से गठबंधन साझोदार भी प्रसन्न हैं। इसे देखते हुए विवास किया जा सकता है कि वे अपने संकुचित क्षेत्रीय या दलीय हितों पर देश के हितों को वरीयता देंगे तथा भारत को विविध देश बनाने में योगदान करेंगे। मोदी सरकार की स्थिति व त्वरित कार्य क्षमता देश के विकास की गारंटी है।

भाजपा की चुनाव मशीनरी ने आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया। अब संवाद की प्रकृति बदल कर इसे सहमति आधारित बनाने की आवश्यकता है।

सिद्धार्थ मिश्रा
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भा जपा की चुनाव मशीनरी ने हालिया लोकसभा चुनाव में आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया जिसका उसे कोई खास लाभ नहीं मिला। चुनाव परिणाम आने और मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद अब संवाद की प्रकृति बदल कर इसे सहमति आधारित बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना देश के लोकांत्रिक इतिहास में उल्लेखनीय है। हालांकि, मतदाताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत से थोड़ा पीछे रखा, यह भाजपा नीत राष्ट्रीय नीतिगत गठबंधन-राजग को बहुमत से कंपते हैं। और उन्होंने इसके सुमित्र संकेत भी दिए हैं।

नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के अंत में ही अगली सरकार के लिए '100 दिन का एंडेंड' तैयार कर लिया था। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं। सभी मंत्रियों को दिया गया था। और उसकी साथ एक बाद इसे विस्तृत विचार-विषय के लिए नीति आयोग के समक्ष रखा जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया में गठबंधन सहयोगियों की राय भिन्नों विकास का पूर्ण समान किया जाएगा। गठबंधन की स्थिति पर आशंका व्यक्त करने वालों को गौर करना चाहिए कि अतीत की तुलना में इस बार गठबंधन के प्रमुख दल- भाजपा की संख्या बहुत अधिक है और गठबंधन सहयोगी अनेक अन्य कारणों से भी इससे बाहर जाना पसंद नहीं करेंगे। तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायदू अंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और भाजपा उनकी सरकार में शामिल है। विवार में जदू नेता नीतिश कुमार राजग गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं और अगले साल हाने वाले विधानसभा चुनाव में भी वे राजग का 'मुख्यमंत्री चेहरा' होंगे। दोनों नेता अपने राज्यों के विकास के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोग चाहते हैं। जिनको देखते ही अगली सरकार ने उनके विवेश करने पर उन लोगों को बहुत राहत मिली है। भारत में अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं। ये दोनों नेता भी कामकाज के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं। सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने पर उन लोगों को बहुत राहत मिली है जिनको देखते ही भारतीय बाजार में आधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

आधिक विकास के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया गया है और इस पर उनके विचार मार्गे गए हैं।

भाजपा के आक्रामक कार्यकाल में जैविक खाद्य बाजार में एंडेंड के लिए केन्द्र से अधिकारिक सहयोगियों को नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देखते ही अधिक सुधारों के लिए एक बड़ा योगदान होता है। यह एंडेंड सभी मंत्रियों को दिया

